Prices of pulses nad vegetables

261. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the extent of rise in prices of pulses and vegetables registered during the last one year and the reasons therefor; and

(b) the steps taken by Government to contain the rising prices of pulses and vegetables?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) According to Wholesale Price Index (base 1981-82), the prices of pulses and vegetables recorded rise of 5.8 per cent and 0.7 per cent respectively during week ending 20th June, 1992 over the same period last year. The increase is generally on account of inflationary trends in the economy.

(b) The Government is seized of the problem and has taken steps for augmenting the supply of pulses and vegetables. The Centrally Sponsored Scheme *viz.* National Pulses Development Programme (NPDP) and Central Sector Scheme *viz.* Special Food Grains Production Programme (SFPP Pulses) are under implementation to increase the production of pulses. Besides, a Central Sector Scheme is also in operation for augmenting production of vegetables.

"एकीकृत धान उत्पादन योजना" के अधीन निधियों का आवंटन

262. **श्री राम नरेश यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष और आगामी वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश तथा बिहार को "समेकित धान उत्पादन योजना" के अंतर्गत आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त राज्यों को अभी तक भुगतान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष धनराशि उन्हें कब तक दे दिये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) एकीकृत धान उत्पादन योजना 1992–93 में राज्यों को, अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत संघटकवार विस्तृत कार्यक्रम के आधार पर, धनराशि निर्मुक्त करना परिकल्पित है । इसलिए, राज्य सरकारों के लिए चालू वर्ष तथा अगले वर्ष के लिए कोई पूर्वनिर्धारित आवंटन नहीं किया गया है । उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम के आधार पर उन्हें अब तक निर्मुक्त की गई धनराशि निम्नानुसार है :–

उत्तर प्रदेश–	318.18	लाख रुपये (तीन करोड़ अट्ठारह लाख तथा अट्ठारह हजार रुपए मात्र)
बिहार	117.13	लाख रुपए (एक करोड़ सत्रह लाख तथा तेरह हजार रुपए मात्र)

(ग) राज्य सरकारों द्वारा जब कभी व्यय संबंधी स्थिति तथा विभिन्न संघटकों के बारे में और सूचना प्रस्तुत की जाएगी तो उन्हें शेष धनराशि निर्मुक्त करने पर विचार किया जाएगा ।

263. [*Transferred to the 14th July, 1992*].

प्राकृतिक आपदा राहत निधि से राज्यों को सहायता दिया जाना

264. **श्री राम नरेश यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को सूखे की समस्या से निपटने के लिए कोई धनराशि उपलब्ध कराई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान इस प्राकृतिक आपदा राहत निधि से राज्यों ने कोई लाभ प्राप्त किया है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सूखे सहित प्राकृतिक आपदायें आने पर राहत उपाय करने के लिए आपदा राहत कोष के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के पास 86.00 करोड़ रुपए का एक वार्षिक आबंटन उपलब्ध है।

(ग) वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश के आपदा राहत कोष के अंतर्गत 86.00-86.00 करोड़ रुपए का वार्षिक आबंटन किया गया है।

Payment to farmers under crop insurance Scheme in Gujarat

265. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of cases are pending for payment of Crop Insurance to the farmers of Gujarat;

(b) if so, the amount due to these farmers; and

(c) by when the Insurance companies are likely to make the payment to the farmers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) to (c) Since implementation of the Comprehensive Crop Insurance Schme (CCIS) in Gujarat w.e.f. 1-4-1985 and upto the end of Rabi 1991-92 an amount of Rs. 576.06 crore was payable, out of which an amount of Rs. 375.42 crore has since been paid to the farmers covered under the scheme in the State. The balance amount of Rs. 200.64 crore is yet to be paid. Action has been initiated to settle these claims after proper scrutiny.

Diversion of land under wheat cultivation to cash crops

266. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been a large scale diversion of land under wheat cultivation to cash crops in recent years;

(b) if so, the details of factors responsible for such shift;

(c) what is the impact of such a diversion on the wheat production; and

(d) what are the steps taken by Government to stop such conversion and its adverse impact on food production?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) No, Sir. There is no evidence of large scale diversion of area under wheat cultivation to cash crops in resent years.

(b) and (c) Does not arise.

(d) The Government is implementing various programmes including supply of subsidised yield increasing inputs like high yielding seeds, fertilisers, plant protection chemicals, transfer of technology, credit and market support in order to increase the productivity and production of various foodgrains including wheat.

Drought in Maharashtra

267. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether a Central Team has visited the drought affected areas of Maharashtra recently;